



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 1997 (अर्षाद 14, 1919)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 1997 (ASADHA 14, 1919)

(इस भाग में प्रिन्ट पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रादेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 421	भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक प्रादेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्रतिकृत पाठ (वेब पलों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ 978
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	605	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और प्रसांविधिक प्रादेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंध और अधोगतन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	601
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	957	भाग III—खण्ड 2—टेंडर कार्यालय द्वारा जारी की गई वेबेस्को और बिजनेसों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	979
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, प्रस्ताव, और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—सूक्ष्म प्रामुखता के अधिकार के प्रयोग प्रयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, प्रस्तावों, और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्रतिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विशेष अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2069
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रचार समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—नैर-परताने व्यक्तियों और नैर-परताने निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	243
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सारोश स्वरूप के प्रादेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—संघीय और हिन्दी बोलों में जन्म और मृत्यु के प्रारंभों को बनाने वाला अनुपूरक	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	421	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	605	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	601
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	957	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	979
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2069
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	243
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1997

संकल्प

सं. एफ. 4(2)/96-रा. भा.—इस विभाग के दिनांक 14-7-93 के संकल्प सं. एफ. 4(4)/92-रा. भा. द्वारा गठित विधि एवं न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने पर भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग एवं विधि कार्य विभाग) के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री

सदस्य

2. कुमारी गिरिजा व्यास, सदस्य, लोक सभा
3. श्रीमती सुषमा स्वराज, सदस्य, लोक सभा
4. श्री वाई. लक्ष्मी प्रसाद, सदस्य, राज्य सभा
5. श्री नागमणि, सदस्य, राज्य सभा
6. श्री चमन लाल गुप्ता, सदस्य, लोक सभा तथा संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य
7. डा. डी. मस्तान, सदस्य, राज्य सभा तथा संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य
8. श्री के. के. शर्मा, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
9. श्री अनंत राम त्रिपाठी, सहायक मंत्री, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, बर्मा
10. श्री माधव पीडल
11. श्री पाण्डुरंग केशव लिमये
12. श्री किशोर कोबले
13. श्री महाबलेश्वर भोरजे
14. श्री बी. के. शर्मा

15. डा. प्रेम कान्त टंडन

16. डा. एन. सुन्दरम्

17. सचिव, विधायी विभाग

18. अपर सचिव, विधायी विभाग

19. संयुक्त सचिव (प्रशासन), विधायी विभाग

20. संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

21. सचिव, विधि कार्य विभाग

22. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग

23. संयुक्त सचिव (राजभाषा अधिकारी) विधि कार्य विभाग

24. सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार, राजभाषा विभाग

25. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

2. राजभाषा खंड के संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

3. समिति का कार्य निम्नलिखित विषयों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना होगा :—

राजभाषा संबंधी संविधान राजभाषा अधिनियम व नियमों में निर्धारित सिद्धांतों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीति निर्णयों तथा गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन तथा मंत्रालय/विभाग में हिन्दी के उत्तरांतर प्रयोग के सम्बन्ध में सलाह देना।

4. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा परन्तु :—

(1) इस समिति में नाम निर्दिष्ट संसद सदस्य, संसद सदस्य न रह जाने पर उसी समय से इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।

(2) अवधि समाप्त होने से पहले रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य शेष रहने अवधि के लिए सदस्य होगा।

5. साधारण

(1) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु यह अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

(2) गैर सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनको स्वीकार्य दरों पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए उच्च स्तरीय प्राप्त समिति के सदस्यों को स्वीकार्य वैयक्तिक भत्ता भी दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति प्रधान मंत्री का कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/योजना आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/निदेशक, लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी. एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 1997

संकल्प

सं. जे-13012/6/97-सामान्य—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बनों पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति को एतद्वारा 10-6-1997 को उसके दो वर्ष की अवधि पूरी करने पर मौजूदा शर्तों पर आगे दो वर्ष की अवधि अर्थात् 10-6-1999 तक के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ाने की स्वीकृति दी जाती है। समिति का गठन निम्नानुसार है:

अध्यक्ष

1. श्री एम. एम. शर्मा
प्रोफेसर रसायन अभियंत्रण एवं निदेशक
रसायन प्रायोगिकी विभाग मूम्बई
विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, मूम्बई

सदस्य

2. डा. ए. पी. कुव्साकर, जीन
(शोध और विकास)
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
पॉंबई, मूम्बई
3. प्रो. के. वासुदेव,
रसायन अभियंत्रण विभागाध्यक्ष भारतीय
प्रायोगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
4. डा. एस. वर्धराजन,
भूतपूर्व मुख्य परामर्शदाता,
योजना आयोग, नई दिल्ली।

5. डा. पाल रत्नास्वामी, उप निदेशक
राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला,
पूणे (महाराष्ट्र)।

6. डा. टी. एस. आर. प्रसाद राव,
निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान
बेहराबून।

7. निदेशक, क्षेत्रीय शोध प्रयोगशाला,
जोरहाट (असम)।

8. डा. ए. वी. रामा राव, निदेशक
रसायन प्रायोगिकी संस्थान,
हैदराबाद।

9. श्री एन. के. शर्मा, निदेशक
राष्ट्रीय शोध विकास निगम,
नई दिल्ली।

10. श्रीमती ललिता बी. सिंह,
सलाहकार (पी. सी.),
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग,
नई दिल्ली।

11. निदेशक (अनु. एवं विकास),
इंडियन पेट्रोकैमिकल्स का. लि., (आर एण्ड डी),
निदेशालय, बड़ोदा।

12. श्री एस. एन. शर्मा, वैज्ञानिक,
तकनीकी उपभाग प्रभाग,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
रफी मार्ग, नई दिल्ली।

13. श्री ए. के. अरोड़ा, निदेशक
(रिफाइनरी एवं पाइपलाइन),
इंडियन आयल का. लि.,
फरीदाबाद।

14. के. के. डींगरा, कार्यकारी निदेशक,
पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ,
नई दिल्ली।

15. डा. एम. जे. जोषडा, निदेशक (तकनीकी),
इंजीनियर्स इंडिया लि.,
नई दिल्ली।

16. श्री के. रवि कुमार, कार्यकारी निदेशक,
उच्च प्रायोगिकी केन्द्र,
नई दिल्ली।

17. तकनीकी विकास महानिदेशालय का नामित,
उद्योग भवन, नई दिल्ली।

18. सचिव का नामिनी,
विज्ञान और प्राकृतिक विभाग,
नई दिल्ली ।

सदस्य सचिव

19. सलाहाकार (रिफाइनेरी),
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव (पेट्रोलियम) संयुक्त सचिवों और सलाहाकार (अन्वेषण) की समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा । अध्यक्ष, समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अथवा समिति की सहायता देने के लिए किसी अन्य व्यक्ती (व्यक्तियों) को भी आमंत्रित कर सकता है ।

3. समिति को सौंपे गए कार्य निम्नीलिखित होंगे :—

“विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों पर और उन्हें हथियों और रसायनों के रूप में हाइड्रोकार्बन के कच्चे माल की अधिकतम संसाधन की सुनिश्चित करने की शीट से कार्यान्वित करने के उपायों पर सलाह देना ।”

4. समिति की बैठकें कभी भी आवश्यकतानुसार आयोजित होंगी परन्तु कम से कम तीन महीनों में एक बार होंगी और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की समय-समय पर उपयुक्त सिफारिशें करेगी ।

5. समिति के लिए आवश्यक अनुसन्धित सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी जाएगी ।

समिति के सदस्यों को किसी प्रकार का पारिवारिक नहीं दिया जाएगा । तथापि, गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । सरकारी अधिकारी/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों पर होने वाले यात्रा भत्ते/दैनिक भत्तों का खर्च संबंधित विभाग/उपक्रम द्वारा वहन किया जाएगा । समिति पर होने वाला खर्च तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा ।

आवेष

आवेष दिया जाता है कि इस गंतव्य को एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आवेष दिया जाता है कि आम सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए ।

पी. एम. मीना
निर्देशक

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1997

सं. ओ-12012/65/96-ओ एन जी डी-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम-5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, तेल भवन, इंदिरापूर (जिसे, इसके बाद ओ एन जी डी लिमिटेड कहा गया है) को पश्चिमी अपट में इंडीए संरचना में 1020 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में 18 नवम्बर, 1996 (18-11-1996) से चार वर्ष के लिए पेट्रोलियम की खोज के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करती है ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का दिया जाता लाइसेंस-धारी को अलग से बनाए जा रहे निबंधनों व शर्तों के अधीन है ।

एम. मार्टिन
डिरेक्टर अधिकारी

दिनांक 20 जून 1997

सं. ओ-12012/52/96-ओ एन जी डी-4—केंद्रीय सरकार एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम-5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, तेल भवन, इंदिरापूर (जिसे, इसके बाद ओ एन जी डी लिमिटेड कहा गया है) को पश्चिमी अपट में 562 वर्ग कि. मी. वाले ब्लॉक जी-9 ब्लॉक में 12 दिसम्बर, 1996 (12-12-1996) से चार वर्ष के लिए पेट्रोलियम की खोज हेतु पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करती है ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का दिया जाता लाइसेंस-धारी को अलग से बनाए जा रहे निबंधनों व शर्तों के अधीन

एम. मार्टिन
डिरेक्टर अधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA

LEGISLATIVE DEPARTMENT
VIDHAYE VIBHAG

New Delhi, the 18th June 1997

RESOLUTION

No. F.4(2)/96-OL.—On the expiry of term of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Law and Justice constituted vide this Department's Resolution No. F.4(4)/92-OL dated 14-7-1993, the Government of India has decided to re-constitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs). The composition of the Samiti will be as follows :—

1. Minister of State for Law and Justice : Chairman
2. Km. Girija Vyas, Member, Lok Sabha. : Member
3. Smt. Sushma Swaraj, Member, Lok Sabha. : Member
4. Shri Y. Laxmi Prasad, Member, Rajya Sabha. : Member
5. Shri Nag Mani, Member, Rajya Sabha. : Member
6. Shri Chaman Lal Gupta, Member, Lok Sabha, and Member of Parliamentary Committee on Official Language. : Member
7. Dr. D. Maitan, Member, Rajya Sabha, and Member of Parliamentary Committee on Official Language. : Member
8. Shri K. K. Grover, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad. : Member
9. Prof. Anant Ram Tripathi, Assistant Secretary, Rashtra Bhasha Prachar Samithi, Wardha. : Member
10. Shri Madhav Pandit. : Member
11. Shri Pandurang Keshev Limaye. : Member
12. Shri Kishore Kolge. : Member
13. Shri Mahabaleshwar Morje. : Member
14. Shri B. K. Sharma. : Member
15. Dr. Prem Kant Tandon. : Member
16. Dr. N. Sundaram. : Member
17. Secretary, Legislative Department. : Member
18. Additional Secretary, Legislative Department. : Member
19. Joint Secretary (Admn.), Legislative Department : Member
20. Joint Secretary & Legislative Counsel Official Languages Wing. : Member
21. Secretary, Department of Legal Affairs. : Member
22. Additional Secretary, Department of Legal Affairs. : Member
23. Joint Secretary (Raj Bhasha Adhikari), Department of Legal Affairs. : Member
24. Secretary and Hindi Adviser to the Government of India, Deptt. of Official Language. : Member
25. Joint Secretary, Deptt. of Official Language. : Member

2. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, will also function as the Secretary of the Samiti.

3 The functions of the Samiti will be to advise the Central Government on matters relating to :—

- (1) tender advice for implementation of the principles relating to Official Languages as given in the Constitution, the Official Language Act and Rules, the

policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/ Department of Official Language relating to Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry/Department.

4. TENURE—The term of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that,

- (i) a member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament; and
- (ii) Members appointed against mid-term vacancies shall be Members for the remaining period of the tenure of the Samiti.

5. GENERAL—(i) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold the meetings at any other station also; and

- (ii) the Non-official Members will be paid travelling allowance by shortest route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance as admissible to members of High Powered Committee for attending the meetings of the Samiti.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to :—

Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat/Ministry of Parliamentary Affairs/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Planning Commission/President's Secretariat/Director of Audit, Central Revenues, New Delhi, and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. L. SAKARWAL
Jt Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the June 1997

RESOLUTION

No. J-13012/6/97-Gen.—The Scientific Advisory Committee on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas on completion of its two years term on 10-6-97, is hereby granted extension for a period of another two years i.e. upto 10-6-99 on the existing terms and conditions. The composition of the Committee will be as under :—

1. Prof. M. M. Sharma,
Professor of Chemical Engineering and
Director, Dept. of Chemical
Technology, University of Mumbai,
Maharashtra. : Member
2. Dr. A. P. Kudchadker, Dean (R&D),
Indian Institute of Technology,
Maharashtra, Mumbai. : Chairman
3. Prof. K. Vasudeva, Head of Chemicals
Engineering Deptt., Indian Institute of
Technology, New Delhi. : Member
4. Dr. S. Varadarajan,
Ex-Chief Consultant,
Planning Commission,
New Delhi. : Member
5. Dr. Paul Ratnaswamy,
Deputy Director,
National Chemical Laboratory,
Pune. : Member

6. Dr. T.S.R. Prasada Rao,
Director,
Indian Institute of Petroleum,
Dehradun. Member
7. Director,
Regional Research Laboratory,
Jorhat, Assam. Member
8. Dr. A. V. Rama Rao,
Director,
Indian Institute of Chemical Technology,
Hyderabad. Member
9. Shri N. K. Sharma,
Director,
National Research Development Corp.,
New Delhi. Member
10. Smt. Lalitha B. Singh,
Adviser (PC),
Deptt. of Chemicals & Petrochemicals,
New Delhi. Member
11. Director (R&D),
Indian Petrochemicals Corpn. Ltd.,
R&D Directorate,
Baroda. Member
12. Shri S. N. Sharma,
Scientist, Technology Utiliation Division,
Council of scientific and Industrial Research,
Rafi Marg,
New Delhi. Member
13. Shri A. K. Aurora,
Director (R&P),
Indian Oil Corporation Ltd.,
Faridabad. Member
14. Shri K. K. Dhingra,
Executive Director,
Petroleum Conservation Research Association,
New Delhi. Member
15. Dr. S. J. Chopra,
Director (Technical)
Engineers India Ltd.,
New Delhi. Member
16. Shri K. Ravi Kumar,
Executive Director,
Centre for High Technology,
New Delhi. Member
17. Nominee of Directorate General of
Technical Development
Udyog Bhavan,
New Delhi. Member
18. Nominee of Secretary,
Deptt. of Science and Technology,
New Delhi. Member
19. Adviser (Refinery),
Ministry of Petroleum and Natural Gas,
New Delhi. Member Secretary

2. Secretary, Petroleum, Additional Secretary/Joint Secretaries and Adviser (Exploration) in the Ministry of Petroleum and Natural Gas will be permanent invitees to the Committee Meetings. The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :—

"To advise on policies relating to Science and Technology and Measures to implement them to ensure optimum processing of hydrocarbon raw material for use as fuels and chemicals".

4. The Committee shall meet as often as necessary but at least once a quarter and will make suitable recommendations to the Ministry of Petroleum and Natural Gas from time to time.

5. The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

6. No remuneration will be paid to the Members of the Committee. However, the expenditure on TA/DA of the non-official members will be met by the Government of India. The TA/DA of Government Official representative of Central Public Sector Undertakings will be met by the concerned Departments/Undertakings. The expenditure on the Committee will be borne by the Oil Industry Development Board (OIDB).

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Government Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P M. MEENA
Director

New Delhi, the 26th May 1997

ORDER

No. O-12012/65/96-ONG.D.IV.—In exercise of powers conferred by clause (I) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Corporation Ltd., Tel Bhavan, Dehradun. (hereinafter referred as O.N.G.C. Ltd.) a Petroleum Exploration Licence to prospect Petroleum for four years with effect from November-18, 1996 (18-11-1996) in ED-A structure area measuring 1020 sq. kms., in West Coast Offshore.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the licensee separately.

M. MARTIN
Desk Officer

The 20th June 1997

ORDER

No. O-12012/52/96-ONG.D.IV.—In exercise of powers conferred by clause (I) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Corporation Limited, Tel Bhavan, Dehradun. (hereinafter referred as O.N.G.C. Ltd.) a Petroleum Exploration Licence to prospect Petroleum for our years with effect from December 12, 1996 (12-12-1996) in WO-9 Block area measuring 562 sq. kms., in Western Offshore.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the licensee separately.

M. MARTIN
Desk Officer

